भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1944
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन योजनाओं की लागत में वृद्धि

†1944. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा किए गए वर्तमान सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनाओं की कुल अनुमानित लागत मूल अनुमान से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 8.29 लाख करोड़ रुपये हो गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने संभावित लागत वृद्धि या धन के दुरुपयोग के संबंध में कोई लेखापरीक्षा या जांच कराई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना था। शुभारंभ के समय, सरकार ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता को भी मंजूरी दी। अनुमोदित केन्द्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग कर लिया गया है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 28.07.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत 12.44 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.96%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को वर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****